इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि अधिनियम सारे देश में एक समान लागू हों। इन क्षेत्रीय कार्यालयों में औषध निरीक्षक भी रखे गये हैं जो राज्य के निरीक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो कि औषध कानून के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार हो।

9. औषध निरीक्षकों के लिये केन्द्रीय औषध नियन्त्रण संगठन द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्य क्रम आयोजित किये जाते हैं। यह एक निरन्तर चलते रहने वाला कार्यक्रम है और राज्य सरकार इस सुविधा का लाभ उठा रही है।

10. ड्रग्स तथा काम्मेटिक्स अधिनियम के अन्तर्गत मिलावटी औषधों के उत्पादन के लिये दंड कैद है जो कि एक वर्ष की अवधि से कम नहीं और दस वर्षों तक हो सकती है। परन्तु न्यायालयों को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वे न्यूनतम से कम भी दंड दे सकते हैं। ऐसी औषधों के उत्पादन में तथा लाने ले जाने उपकरणों तथा सामान को सख्त किया जा सकता है परन्तु अब अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे नकली औषधों का उत्पादन करने वालों को कड़ा दंड दिया जा सके। न्यायालयों को जो विवेकाधिकार प्राप्त है उन्हें भी समाप्त करने का प्रस्ताव है। औषध निरीक्षकों के अधिकारों को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। इसके लिये संशोधन विधेयक का एक मसौदा तैयार किया गया है।

Cases pending in Supreme Court and High Courts

299. SHRI D. AMAT: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of cases pending in Supreme Court of India;

(b) what are the causes for the delay in their disposal; and

(c) whether Government propose to appoint on an *ad-hoc* basis more judges to clear the backlog in disposal of cases in Supreme Court and High Courts, if not, what other steps the Government propose to take in the matter?

THE MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) The numebr of regular hearing matters pending on 1st November, 1978 in the Supreme Court was 14,833.

(b) The major cause for delay in disposal has been an increase in institutions over years. The institutions increased from 3,241 in 1960 to 14,501 in 1977 without proportionate and timely increase in the judge strength.

(c) Appointment of retired judges to sit and act as judges of the Supreme Court and High Courts is made by the respective Chief Justices in accordance with the provisions of articles 128 and 224-A with the previous consent of the President. At present there is no proposal for the appointment of an *ad-hoc* judge in the Supreme Court. There is one *ad-hoc* judge in the Gauhati High Court. Besides this, proposals for appointment of two *ad-hoc* judges in the Andhra Pradesh High Court and one *ad-hoc* judge in the Patna High Court are under consideration. Proposals received for the appointment of judges under these provisions of the Constitution are given expeditious consideration. Other steps taken by the Government to speed up the disposals are given in the attached Statement.

Statement

The following steps have been taken to speed up the disposal of cases:-

(i) The sanctioned Judge strength of the Supreme Court has been raised from 13 to 17 (excluding the Chief Justice) with effect from the 31 December, 1977 by amending the Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956. The vacancies occuring on 1-1-1978 and 22-2-1978 on the retirement of Justice Goswami and Justice M. H. Beg as well as two of the newly created posts have been filled.

(ii) A substantial number of vacancies in the High Courts have been filled up. Initiative has been taken by the Central Government to call for proposals from the State Authorities/ Chief Justices and wherver required reminders have been issued to the concerned State Authorities/Chief Justices. During the period from 1st April, 1977 to 15th November, 1978 as many as 86 fresh appointments have been made.

(iii) The judge strength have also been increased since 1-4-1977 in the High Courts in respect of which proposals were received. This increase has been made in the following High Courts from the dates the posts are filled up.

Name of the High Court	Increased by	
	Pmt	Addl
Allahabad		9
Madhya Pradesh		6
Karnataka	1	1
Himachal Pradesh		2
Patna		3
Rajasthan.		1
Delhi		1
TOTAL	1	23
	24	

(iv) Letters have been addressed to the Bar Councils and Bar Assiciations of various States requesting them for cooperation and also for suggestions for speedy disposal of cases.

(v) The Law Commission have been requested to suggest suitable measures to tackle the general problem of arrears. They are seized of the matter.

(vi) The Supreme Court, with the approval of the President, has recently amended the Supreme Court Rules to facilitate early disposal of cases in the Supreme Court.

रेल यातायात में अनियमितताओं को दूर करने के लिए अभियान

300. **श्री सुरेन्द्र भा सुमन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल विभाग ने रेल यातायात में अनियमितताओं को दूर करने तथा गाड़ियों के ठीक समय पर चलने और पहुंचने को सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान चलाया है;

(ख) उसके परिणामस्वरूप गाड़ियों के समय पर चलने की स्थिति में कितना तुलनात्मक सुधार हुआ है; और

(ग) पहले के महीनों की तुलना में नियमित एवं अनियमित गाड़ियों की स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां, गाड़ियों के चालन पर सभी स्तरों पर निकटता से निगाह रखने और उनके चालन में सुधार लाने के लिए 1-6-1978 से सभी रेलों पर एक विशिष्ट समय पालन अभियान चलाया गया है ।

(ख) इस अभियान के परिणामस्वरुप, विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार हुआ और उसका प्रतिशत मई, 1978 की तुलना में अक्तूबर, 1978 के दौरान बड़ी लाइन पर 2.4 परसेंट से 16.6 परसेंट के बीच और मीटर लाइन पर 3.1 परसेंट से 9.2 परसेंट के बीच रहा ।

(ग) मई, 1978 की तुलना में, अक्तूबर, 1978 के महीने 'समय न खोने वाली' मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का रेलवे-वार समय-पालन इस प्रकार है:—

रेलवे	बड़ी लाइन		मीटर लाइन	
	मई, 78	अक्तूबर, 78	मई, 78	अक्तूबर, 78
मध्य	74.3	89.3	—	—
पूर्व	78.1	84.6	—	—
उत्तर	90.7	94.4	93.2	96.3
पूर्वोत्तर	94.6	97.0	79.3	76.0
पूर्वोत्तर सीमा	73.8	85.8	89.2	88.6
दक्षिण	83.2	88.1	84.1	93.3
दक्षिण-मध्य	80.0	84.0	86.0	90.0
दक्षिण-पूर्व	85.9	96.3	—	—
पश्चिम	80.7	87.3	85.0	94.0